

नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

वर्ष : 01
अंक : 337
दि. 10.04.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

“यूपी पुलिस में बड़ा प्रशासनिक ‘रीसेट’: 12 आईपीएस के तबादले से बदली जिलों की कमान”

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए पुलिस विभाग में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस बदलाव के तहत 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले ने न केवल विभाग के भीतर हलचल पैदा कर दी है, बल्कि कई जिलों की पुलिस व्यवस्था की कमान भी नए हाथों में सौंप दी गई है। अचानक हुए इस निर्णय को प्रशासनिक रणनीति के तहत एक अहम कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना है। इस फेरबदल में तीन अपर पुलिस अधीक्षक (ASP), चार सहायक पुलिस अधीक्षक और पांच सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। शासन का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर

लगातार सतर्कता बरती जा रही है और विभिन्न जिलों में पुलिसिंग को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने की जरूरत महसूस की जा रही है। तबादलों की सूची में सहारनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) Sagar Jain को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। वहीं गोंडा पूर्वी के अपर पुलिस अधीक्षक Manoj Kumar Rawat को संभल में अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरठ में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक Ayush Vikram Singh को बहराइच का अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) बनाया गया है। इसी क्रम में सीतापुर के सहायक पुलिस अधीक्षक Vinayak Gopal Bhosale को मेरठ में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के रूप में तैनात किया गया है। मेरठ के सहायक पुलिस अधीक्षक Antariksh Jain को बुलंदशहर का अपर पुलिस



अधीक्षक (ग्रामीण) बनाया गया है। संभल के सहायक पुलिस अधीक्षक Alok Kumar को प्रतापगढ़ का अपर पुलिस

अधीक्षक (नगर पूर्वी) नियुक्त किया गया है। अलीगढ़ के सहायक पुलिस अधीक्षक

Mayank Pathak को सहारनपुर में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) की जिम्मेदारी दी गई है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में

सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात Lipi Nagayach को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के सहायक पुलिस आयुक्त Twinkle Jain को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त के रूप में नई तैनाती मिली है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के सहायक पुलिस आयुक्त Rajkumar Meena को मिर्जापुर में अपर पुलिस अधीक्षक (नक्सल) बनाया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के सहायक पुलिस आयुक्त Rishabh Runwal को सोनभद्र का अपर पुलिस अधीक्षक (नक्सल) नियुक्त किया गया है, जबकि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के सहायक पुलिस आयुक्त Ishan Soni को जालौन का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इस व्यापक फेरबदल को केवल तबादला नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक पुनर्संरचना के

रूप में देखा जा रहा है। पुलिस विभाग में इस तरह के बदलाव अक्सर कार्यक्रमता बढ़ाने, नए दृष्टिकोण लाने और संवेदनशील जिलों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती के उद्देश्य से किए जाते हैं। खासतौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र में नए अधिकारियों की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि सरकार इन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना चाहती है। गौरतलब है कि इस बड़े पुलिस फेरबदल से ठीक एक दिन पहले राज्य सरकार ने पांच आईएएस अधिकारियों को भी तबादला किया था। इसमें Gunjan Dwivedi को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का मिशन निदेशक बनाया गया, जबकि Ratnesh Singh को प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में अपर निदेशक की जिम्मेदारी दी गई। Ashok Kumar को विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के साथ कारागार प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

इसी तरह Girijesh Kumar Tyagi को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सचिव नियुक्त किया गया, जबकि Anita Verma Singh को उच्च शिक्षा विभाग में उद्देश्य से किए जाते हैं। राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय की कुलसचिव बनाया गया है। लगातार हो रहे इन प्रशासनिक फेरबदल से यह साफ संकेत मिल रहा है कि सरकार शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। पुलिस और प्रशासन दोनों स्तरों पर किए गए ये बदलाव आने वाले समय में कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों और जनसेवाओं पर सकारात्मक असर डाल सकते हैं। अब नजर इस बात पर होगी कि नई तैनातियां जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव डालती हैं और क्या ये बदलाव प्रदेश में संसाधन विभाग के साथ कारागार प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

“पंजाब में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम: बीकेआई मॉड्यूल का भंडाफोड़, आईएसआई कनेक्शन से बड़ी चिंता”

चंडीगढ़। पंजाब में एक बार फिर आतंकवाद के साथे को गहराने की कोशिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते विफल कर दिया। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क कर दिया है। इस कार्रवाई में Babbar Khalsa International (बीकेआई) से जुड़े एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी Inter-Services Intelligence (आईएसआई) का समर्थन प्राप्त था। पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान दो आरोपियों—Akash Masih और Jabloun—को गिरफ्तार किया है, जो गुरदासपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस मॉड्यूल में ऐसे लोगों को शामिल किया गया था, जो पहले से गैरकानूनी गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक Gaurav Yadav के अनुसार, यह कार्रवाई अतृप्त ग्रामीण पुलिस, गुरदासपुर पुलिस और State Special Operations Cell Punjab (SSOC) की संयुक्त टीम द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि यह मॉड्यूल विदेशों में बैठे हैडलर्स के निर्देश पर काम कर रहा था और



इसका उद्देश्य राज्य में बड़े स्तर पर हिंसा फैलाना था। जांच के दौरान जो बरामदगी हुई है, उसने इस साजिश की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया है। आरोपियों के पास से पांच हथियारों, दो डेटोनेटर और आईईडी (इम्प्लोवाइंड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बरामद की सामग्री मिली है। यह संकेत देता है कि हमले की योजना केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि क्रियान्वयन के वेवद करीब थी। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यदि यह साजिश सफल हो जाती, तो इसके परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे। बॉर्डर रेंज के डीआईजी Sandeep Goel ने

भर्ती किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर विदेशों में बैठे हैडलर्स उन्हें निर्देश, फंडिंग और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इस पूरी शृंखला को तोड़ना ही सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चुनौती होती है। फिलहाल, पुलिस इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य संभावित सदस्यों की तलाश में जुटी है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि किन-किन स्थानों को निशाना बनाया जाना था। साथ ही, वित्तीय लेन-देन, डिजिटल कम्युनिकेशन और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी गहन जांच की जा रही है। यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि भीतर भी उतनी ही गंभीरता से लड़ी जाती है। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया, लेकिन यह भी साफ है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। पंजाब, जिसने अतीत में आतंकवाद का दर्द झेला है, आज फिर ऐसे प्रयासों का सामना कर रहा है। हालांकि, इस बार सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत और सजग है। सरकार और एजेंसियों का स्पष्ट संदेश है—देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, और जो भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसे कानून के कठोर दायरे में लाया जाएगा।

“क्वांटम युग की दहलीज पर भारत: 14 अप्रैल को लॉन्च होगा पहला स्वदेशी ओपन-एक्ससेस क्वॉंटम कंप्यूटर”

अमरावती। भारत अब तकनीकी क्रांति के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से भविष्य की दिशा बदलने वाली है। 14 अप्रैल को देश का पहला स्वदेशी ‘ओपन-एक्ससेस’ क्वॉंटम कंप्यूटर लॉन्च होने जा रहा है, जो न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी एक नई रूंचाई देता है। ‘अमरावती क्वॉंटम रेंफ़रेंस फैसिलिटी’ के तहत विकसित अमरावती 1एस और 1क्यू नामक ये सिस्टम भारत को वैश्विक क्वॉंटम तकनीक की दौड़ में मजबूती से खड़ा करने वाले हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें उपयोग किए गए 80 प्रतिशत से अधिक पुर्जे पूरी तरह स्वदेशी हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक क्वॉंटम हार्डवेयर के क्षेत्र में भारत काफी हद तक विदेशी तकनीक पर निर्भर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार के इस प्रयास ने यह साबित कर दिया है कि सही रणनीति और संसाधनों के साथ भारत अत्याधुनिक तकनीक में आत्मनिर्भर बन सकता है। इस परियोजना को लेकर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu के सचिव P. S. Pradyumna ने बताया कि अप्रैल 2025 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट ने

बेहद कम समय में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के वैज्ञानिक इकोसिस्टम के लिए एक नई शुरुआत है। क्वॉंटम कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पारंपरिक कंप्यूटरों से पूरी तरह अलग होती है। जहां सामान्य कंप्यूटर ‘बिट’ पर काम करते हैं, वहीं क्वॉंटम कंप्यूटर ‘क्यूबिट’ का उपयोग करते हैं, जो एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकते हैं। इसी कारण ये मशीनें जटिल समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर सकती हैं—चाहे वह दवा खोज (drug discovery) हो, जलवायु मॉडलिंग, साइबर सुरक्षा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उन्नत विकास। इन क्वॉंटम सिस्टम की सबसे अद्भुत विशेषता उनका तापमान है। ये मशीनें लान्थाना माइसिन 273 डिग्री सेल्सियस (absolute zero के करीब) पर काम करती हैं। इतना कम तापमान बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो क्यूबिट्स को स्थिर और त्रुटिरहित बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह वही तापमान सीमा है, जहां भौतिकी के नियम भी अलग तरह से व्यवहार करते हैं और क्वॉंटम प्रभाव स्पष्ट

रूप से दिखाई देते हैं। यह सुविधा भारत के पहले पूर्ण विकसित क्वॉंटम हार्डवेयर टेस्टबेड के रूप में कार्य करेगी। इसका उपयोग न केवल अनुसंधान के लिए किया जाएगा, बल्कि नई तकनीकों के परीक्षण, सत्यापन और प्रमाणन के लिए भी किया जाएगा। अब तक भारत के पास इस स्तर की कोई स्वदेशी सुविधा नहीं थी, जिससे वैज्ञानिकों को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस परियोजना को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने वैश्विक तकनीकी कंपनियों IBM और Tata Consultancy Services के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इससे न केवल तकनीकी सहयोग मिलेगा, बल्कि भारतीय इकोनॉमी में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दशक में क्वॉंटम कंप्यूटिंग दुनिया की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक होगी। ऐसे में भारत का इस क्षेत्र में समय रहते कदम उठाना एक दूरदर्शी निर्णय है। यह केवल एक मशीन का लॉन्च नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है—जहां क्वॉंटम की सीमाएं टूटेंगी और संभावनाओं का विस्तार अनंत होगा। अंततः, 14 अप्रैल का यह दिन भारतीय विज्ञान और तकनीक के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह वह क्षण होगा जब भारत न केवल तकनीक का उपभोक्ता, बल्कि उसका निर्माता और मार्गदर्शक बनने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा।

“चुनाव आयोग पर उठे सवाल: ‘राज्य के भीतर राज्य’ बनने के आरोप से गरमाई सियासत”

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रशासनिक स्तर पर हुए एक अहम फैसले ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। चुनाव आयोग द्वारा राज्य के मुख्य सचिव के अचानक तबादले को लेकर न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मची है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की सीमाओं और अधिकारों पर भी गहन चर्चा शुरू हो गई है। इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P. Chidambaram, जिन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला है। P. Chidambaram ने चुनाव आयोग को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उसे ‘इम्पेरियम इन इम्पेरियो’ यानी ‘राज्य के भीतर राज्य’ की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनका यह बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर उठाया गया गंभीर सवाल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार जरूर है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है और इसे संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब Election Commission of India ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव N. Muruganandam का अचानक तबादला कर दिया और उनकी जगह Mysai Kumar को नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। मुगुनंदम को एक ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी के रूप में जाना जाता रहा है, ऐसे में उनका अचानक हटाया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। P. Chidambaram ने अपने बयान में



Supreme Court of India के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल संतुलित तरीके से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग को खुद को एक स्वतंत्र सत्ता केंद्र के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर कार्य करना चाहिए। इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M. K. Stalin ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले को ‘लोकतंत्र के लिए शर्मनाक’ करार देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई से निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। उनका तर्क है कि यदि चुनाव आयोग को किसी अधिकारी के कामकाज पर संदेह था, तो ऐसी ही कार्रवाई अन्य चुनावी राज्यों—जैसे Assam—में क्यों

नहीं की गई। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह कदम राजनीतिक प्रेरणा से लिया गया है और इसके पीछे केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष दबाव हो सकता है। P. Chidambaram ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का यह रवैया राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अनावश्यक दखल के समान है, जो संघीय ढांचे की भावना के विपरीत है। यह विवाद केवल एक तबादले तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने एक बड़े संवैधानिक प्रश्न को जन्म दिया है—क्या चुनाव आयोग अपने अधिकारों का विस्तार कर रहा है, या वह निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग को बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन इस

अधिकार का प्रयोग पारदर्शिता और संतुलन के साथ होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। जहां एक ओर चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की है, वहीं दूसरी ओर उसे अपने अधिकारों की सीमाओं का भी ध्यान रखना होता है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद आगे किस दिशा में जाता है—क्या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर यह मामला न्यायिक हस्तक्षेप तक पहुंचेगा। लेकिन इतना तय है कि इस बहस ने लोकतंत्र, संविधान और संस्थाओं की भूमिका पर एक बार फिर देशव्यापी चर्चा को जन्म दे दिया है।



नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी



JioTV
CHENNAL NO. 2063



Jio Air Fiber



Jio Tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

“कफ सिरप कांड में शिकंजा कसता हुआ: इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घिरा सरगना”

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जुड़े चर्चित कफ सिरप तस्करि कांड ने अब अंतरराष्ट्रीय रूप ले लिया है। इस मामले के मुख्य आरोपी Shubham Jaiswal के खिलाफ INTERPOL द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने के बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई और तेज हो गई है। यह नोटिस किसी भी फरार आरोपी के खिलाफ वैश्विक स्तर पर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का एक सशक्त कानूनी माध्यम माना जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह केवल अब उसके बच निकलने के रास्ते बेहद सीमित हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, Shubham Jaiswal लंबे समय से फरार चल रहा था और जांच एजेंसियों को आशंका है कि वह फिलहाल Dubai में छिपा हुआ है। इस जानकारी के आधार पर भारतीय एजेंसियां अब स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित कर रही हैं, ताकि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके।

इस पूरे मामले की जांच में एक बड़े और संगठित तस्करि नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई में लंबे समय से सक्रिय था। इस नेटवर्क का संचालन बेहद सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था, जिसमें अलग-अलग राज्यों और संभावित रूप से अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी शामिल थे। भारी मात्रा में बरामद की गई नशीली सिरप इस बात का संकेत देती है कि यह केवल स्थानीय स्तर का अपराध नहीं, बल्कि एक व्यापक अवैध कारोबार का हिस्सा था। Shubham Jaiswal को इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसके खिलाफ वाराणसी में कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हैं और पुलिस पहले ही इस मामले में कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन मुख्य सरगना के फरार रहने से जांच अधूरी मानी जा रही थी।



रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अब इस मामले में नई गति आ गई है। यह नोटिस दुनिया भर की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को अलर्ट करता है कि संबंधित व्यक्ति वांछित है और उसे गिरफ्तार किया जाना है। इसके बाद अब अगला बड़ा कदम प्रत्यर्पण (Extradition) प्रक्रिया का होगा। भारतीय एजेंसियां Dubai के स्थानीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर रही हैं, ताकि आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत लाया जा सके। यह प्रक्रिया जटिल होती है और इसमें दोनों देशों के बीच कानूनी समझौते, दस्तावेजी साक्ष्य और अदालत की अनुमति शामिल होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि Shubham Jaiswal को गिरफ्तारी हो जाती है, तो इस पूरे नेटवर्क के कई और राज खुल सकते हैं—जैसे फंडिंग का स्रोत, सप्लाई चेन और इसमें शामिल अन्य बड़े नाम। इससे न केवल इस गिरोह का पूरी तरह सफाया किया जा सकेगा, बल्कि भविष्य में इस तरह के अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

यह मामला यह भी दिखाता है कि किस तरह नशीली दवाओं का अवैध कारोबार समाज के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। कफ सिरप (Extradition) प्रक्रिया का होगा। भारतीय एजेंसियां Dubai के स्थानीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर रही हैं, ताकि आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत लाया जा सके। यह प्रक्रिया जटिल होती है और इसमें दोनों देशों के बीच कानूनी समझौते, दस्तावेजी साक्ष्य और अदालत की अनुमति शामिल होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि Shubham Jaiswal को गिरफ्तारी हो जाती है, तो इस पूरे नेटवर्क के कई और राज खुल सकते हैं—जैसे फंडिंग का स्रोत, सप्लाई चेन और इसमें शामिल अन्य बड़े नाम। इससे न केवल इस गिरोह का पूरी तरह सफाया किया जा सकेगा, बल्कि भविष्य में इस तरह के अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

“गैस संकट पर सख्ती: मंत्री इरफान अंसारी का अल्टीमेटम, 10 दिन में व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश”

रांची। झारखंड में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर उत्पन्न संकट ने आम लोगों की परेशानी को चरम पर पहुंचा दिया है। ऐसे में राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री Irfan Ansari ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों और गैस एजेंसियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है—या तो व्यवस्था सुधरे, या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री का तेवर इतना तीखा था कि उन्होंने सीधे 7 से 10 दिनों का अल्टीमेटम दे डाला। बैठक में सामने आए आंकड़ों ने स्थिति की गंभीरता को उजागर कर दिया। राजधानी रांची से लेकर औद्योगिक शहर Jamshedpur और Dhanbad तक, उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए 15 से 20 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। यह देरी केवल असुविधा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित करने वाली समस्या बन चुकी है। मंत्री Irfan Ansari ने इसे “उपभोक्ताओं के साथ अन्याय” करार देते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित डिलीवरी को “युद्धस्तर” पर खत्म किया जाए



और आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) को तुरंत दुरुस्त किया जाए। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कागजी सुधार नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव दिखाई देना चाहिए। उन्होंने जिला स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए, ताकि हर दिन की प्रगति पर नजर रखी जा सके। मौजूदा समय में शायी-ब्याह और धार्मिक आयोजनों का सीजन होने के कारण गैस की मांग और बढ़

गई है। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्री Irfan Ansari ने विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरों पर किसी भी परिवार को गैस के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे शायी या धार्मिक आयोजनों से जुड़े उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराएं। लेकिन इस पूरे संकट के बीच सबसे गंभीर मुद्दा कालाबाजारी

और अवैध वितरण का है। मंत्री ने इस पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए साफ चेतावनी दी है कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल उपभोक्ता के पते पर ही की जानी चाहिए। यदि कहीं भी सड़क पर, चौराहों पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर अवैध तरीके से सिलेंडर बांटे जाते पाए गए, तो संबंधित एजेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बिचौलियों द्वारा की जा रही जमाखोरी

(hoarding) पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छापेमारी अभियान चलाने के लिए जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, ताकि अवैध भंडारण और काले बाजार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। मंत्री ने दो टूक कहा कि “आम जनता की जरूरतों के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूत्र में बख्शा नहीं जाएगा।” विशेषज्ञों का मानना है कि गैस आपूर्ति में आई इस समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं—जैसे लॉजिस्टिक बाधाएं, मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन, या वितरण प्रणाली में खामियां। लेकिन यदि इन समस्याओं को समय रहते नहीं सुलझाया गया, तो यह संकट और गहरा सकता है। अब सचकी नजरें अगले 10 दिनों पर टिकी हैं। क्या एजेंसियां और अधिकारी इस चुनौती को समय पर पूरा कर पाएंगे, या फिर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? यह आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और जनता को राहत दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। इसी सिद्धांत के तहत अदालत ने

“सोमा मुंडा हत्याकांड: हाईकोर्ट से देवव्रत नाथ शाहदेव को राहत, जमानत के साथ कई सख्त शर्तें लागू”

रांची। झारखंड के चर्चित और संवेदनशील सोमा मुंडा हत्याकांड में एक अहम कानूनी मोड़ सामने आया है, जहां Jharkhand High Court ने आरोपी Devvrat Nath Shahdeo को जमानत दे दी है। यह फैसला न केवल इस बहुचर्चित मामले को प्रभावित करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया और आरोपियों के अधिकारों के संतुलन को भी सामने लाता है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति Anil Kumar Choudhary की अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों—प्रार्थी और राज्य सरकार—की दलीलों को गंभीरता से सुना गया। अदालत के समक्ष यह तर्क रखा गया कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और ट्रायल की प्रक्रिया अभी जारी है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए मामले की गंभीरता और सामाजिक प्रभाव को रेखांकित किया गया। गौरतलब है कि खूंटी जिले में हुए इस हत्याकांड ने स्थानीय स्तर पर व्यापक चर्चा और तनाव को जन्म दिया था। Khunti जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस प्रकार की घटना ने कानून-व्यवस्था और सामाजिक समरसता पर भी सवाल खड़े किए थे। सोमा मुंडा की हत्या को लेकर पुलिस ने विस्तृत जांच की थी और कई पहलुओं का ध्यान में रखते हुए आरोपियों की भूमिका को चिन्हित किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर अवश्य हैं, लेकिन जमानत का सिद्धांत “बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन” के आधार पर तय किया जाता है। इसी सिद्धांत के तहत अदालत ने



सुनिश्चित किया कि आरोपी को जमानत दी जाए, लेकिन इसके साथ ही कड़े नियमों का पालन अनिवार्य किया जाए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि Devvrat Nath Shahdeo को 25,000 रुपये के दो निजी मुचलकों के साथ जमानत दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ट्रायल के दौरान हर सुनवाई में उपस्थित रहें और जांच में पूरा सहयोग करें। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो जमानत तुरंत रद्द की जा सकती है। इस फैसले के बाद जहां एक ओर आरोपी पक्ष को राहत मिली है, वहीं पीड़ित पक्ष और समाज के कुछ वर्गों में चिंता भी देखी जा रही है। ऐसे मामलों में जमानत का निर्णय हमेशा संवेदनशील होता है, क्योंकि यह न्याय और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती

प्रस्तुत करता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को दर्शाता है। अदालत ने न तो मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया और न ही आरोपी के मौलिक अधिकारों को। इस प्रकार का संतुलित दृष्टिकोण ही न्यायपालिका की मजबूती का आधार होता है। अब इस पूरे मामले की निगाहें आगामी ट्रायल पर टिकी हैं, जहां साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल, जमानत मिलने के बाद Devvrat Nath Shahdeo को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह मामला एक बार फिर यह याद दिलाता है कि न्याय की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है, लेकिन हर कदम पर कानून का पालन और संतुलन बनाए रखना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली पहचान है।

“बीरभूम से पीएम मोदी की तीखी हुंकार: घुसपैठ, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार, बंगाल की राजनीति में तेज हुआ टकराव”

बीरभूम। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गरमा गई है, जब प्रधानमंत्री Narendra Modi ने बीरभूम की धरती से एक बेहद आक्रामक और भावनात्मक भाषण देते हुए राज्य की मौजूदा व्यवस्था, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सीधे प्रहार किए। उनकी यह जनसभा न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि इसमें दिए गए संदेशों ने आगामी चुनावी माहौल को भी पूरी तरह से प्रभावित करने के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत ही एक सख्त चेतावनी के साथ की। उन्होंने कहा कि “घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा और उनके आका, जो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जाएगा।” यह बयान केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि एक राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि एक कर्मजोब कर्मजोब का प्रयास था, जिसे भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से पश्चिम बंगाल में उठाती रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि घुसपैठ के कारण स्थानीय लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए कम मजदूरी पर काम करके स्थानीय युवाओं से रोजगार छीन रहे हैं, जिसके कारण यहां के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने Rampurhat और Malda का जिक्र करते हुए कानून-

व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जो घटनाएं इन क्षेत्रों में सामने आई हैं, उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यहां तक कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को भी बंधक बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि राज्य में कानून का शासन कमजोर हो गया है। प्रधानमंत्री का भाषण केवल सुरक्षा और घुसपैठ तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सामाजिक मुद्दों को भी उठाते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं, खासकर SC ST OBC communities की बेटियों के लिए हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीर नहीं है और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने Trinamool Congress पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी अहंकार में डूबी हुई है और उसने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति Droupadi Murmu का भी अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने इसे न केवल एक व्यक्ति का अपमान बताया, बल्कि पूरे आदिवासी समाज और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि यह मानसिकता दर्शाती है कि सत्ता में बैठे लोग किस तरह से सामाजिक संवेदनाओं को नजरअंदाज

कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं इन क्षेत्रों में सामने आई हैं, उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यहां तक कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को भी बंधक बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि राज्य में कानून का शासन कमजोर हो गया है। प्रधानमंत्री का भाषण केवल सुरक्षा और घुसपैठ तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं, खासकर SC ST OBC communities की बेटियों के लिए हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीर नहीं है और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने Trinamool Congress पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी अहंकार में डूबी हुई है और उसने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति Droupadi Murmu का भी अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने इसे न केवल एक व्यक्ति का अपमान बताया, बल्कि पूरे आदिवासी समाज और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि यह मानसिकता दर्शाती है कि सत्ता में बैठे लोग किस तरह से सामाजिक संवेदनाओं को नजरअंदाज

विपरीत, उन्होंने केंद्र सरकार की रोजगार योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि पिछले 2-2.5 वर्षों में देशभर में रोजगार मेलों के माध्यम से 17 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों दी गई हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी वादा किया कि यदि राज्य में “डबल इंजन सरकार” बनती है, तो बंगाल में भी बड़े पैमाने पर रोजगार मेलों आयोजित किए जाएंगे और सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बंगाल को लूट “जिन-जिन लोगों ने बंगाल को लूटा है, उनका हिसाब किया जाएगा।” यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि यदि सत्ता परिवर्तन होता है, तो भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगामी चुनावों की तारीखों—23 अप्रैल और 29 अप्रैल—का जिक्र करते हुए कहा कि यह चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि बंगाल के भविष्य को तय करने का अवसर है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने वोट का इस्तेमाल सोच-समझकर करें और राज्य को एक नई दिशा दें।

लखनऊ की आग में जलते सपने: फीनिक्स मॉल के पास सब्जी मंडी में भीषण हादसे ने उजाड़ दी दर्जनों जिंदगियां

लखनऊ को उस भयानक रात ने एक बार फिर यह सख्त कर दिया कि एक छोटी सी चूक किस तरह सैकड़ों परिवारों की दुनिया उजाड़ सकती है। कृष्ण नगर थाना क्षेत्र में फीनिक्स यूनाइटेड मॉल के पास स्थित विशाल सब्जी मंडी में गुरुवार रात लगी आग ने पूरे इलाके को दहला दिया। रात करीब 10 बजे शुरू हुई यह आग कुछ ही मिनटों में इतनी विकराल हो गई कि लोगों को संपलने का मौका तक नहीं मिला। यह मंडी केवल एक बाजार नहीं थी, बल्कि सैकड़ों परिवारों की आजीविका का केंद्र थी। करीब 50 हजार स्वकार फ्लैट में फैली इस मंडी में रोजाना लगभग 200 दुकानें लगती थीं। यहां फल, सब्जी, अनाज और किराने के व्यापारी अपनी मेहनत से जीवन यापन करते थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को ज्ञापित किया, तो इन दुकानों के साथ-साथ लोगों के बच्चों की मेहनत और सपने भी राख में बदलने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुरुआत में हल्का धुआं उठता दिखाई दिया, जिसे लोगों ने सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में आग ने अचानक विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते एक दुकान से उठी लपटें दूसरी दुकानों तक पहुंच गईं और पूरी मंडी को अपनी गिरफ्त में लेने लगीं। मंडी में मौजूद प्लास्टिक की बोतलियां, गते और अन्य ज्वलनशील सामान ने आग को और अधिक घटकों का काम किया। घटना का सबसे डरावना पहलू था लगातार हो रहे धमाके। लोगों के अनुसार, करीब 10 से 12 जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इन धमाकों की वजह गैस सिलेंडरों के फटने को माना जा रहा है। हर धमाके के साथ



लोग और ज्यादा डर जाते थे और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते थे। कुछ ही मिनटों में पूरा बाजार अफ्न-तफ्नो और चौख-पुखर से भर गया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें और घना धुआं करीब 3 किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई दे रहा था। आसमान में उठता काला धुआं इस बात का संकेत दे रहा था कि अंदर क्या भयानक स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। कृष्ण नगर, आलमबाग और पीजीआई फायर स्टेशन से करीब 10 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। धक्कल कर्मियों ने लगातार तीन घंटे तक की मशक्कत की, तब जकार आग पर काबू पाया जा सका। यह कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि आग तेजी से फैल रही थी और बीच-बीच में ही रहे धमाके हालात को और अधिक खतरनाक बना रहे थे। जब तक आग बुझाई गई, तब तक लगभग 50

था? ये सवाल केवल इस मंडी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शहर के अन्य बाजारों पर भी लागू होते हैं। लखनऊ जैसे बड़े शहर में इस तरह की घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी तैयारियां कितनी मजबूत हैं। अक्सर देखा जाता है कि फायर सेफ्टी के नियमों को नजरअंदाज किया जाता है और हादसे के बाद ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात होती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस हादसे ने उन छोटे व्यापारियों की जिंदगी को गहराई से प्रभावित किया है, जो रोज की कमाई पर अपने परिवार का पेट पालते हैं। उनके लिए यह सिर्फ दुकान नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी दुनिया थी। अब जब सब कुछ जलकर राख हो गया है, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे फिर से कैसे शुरुआत करेंगे। इस हादसे ने आग और प्रशासन के सामने अब बड़ी जिम्मेदारी है कि वे इन पीड़ितों की हर संभव मदद करें। मुआवजा, पुनर्वास और नई शुरुआत के लिए सहायता देना बेहद जरूरी है। साथ ही, भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम और उनकी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। लाने का कारण माना जा रहा है। एक दुकान में हुए शॉर्ट सर्किट ने धीरे-धीरे आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते यह आग एक बड़े हादसे में बदल गई। यह घटना कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। क्या इस मंडी में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम थे? क्या फायर सेफ्टी के नियमों का पालन किया जा रहा था? क्या इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के रखना सही अनिवार्य जिम्मेदारी है।

“खजाना खाली, सिस्टम चौपट”: अररिया कांड पर तेजस्वी का हमला, बिहार की व्यवस्था पर उठाए तीखे सवाल”

पटना। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा गई है, जहां Tejashwi Yadav ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रशासनिक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और आर्थिक हालात को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अररिया में हुई हत्या की घटना को आधार बनाकर उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और दावा किया कि बिहार का सिस्टम पूरी तरह से चरमरा चुका है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं से बेखबर होकर केवल अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है और इसका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है, जिन्हें समय पर वेतन तक नहीं मिल पा

रहा। उनके अनुसार यह स्थिति प्रशासनिक विफलता का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि जब किसी राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, तो उसका प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ता है—चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या कानून-व्यवस्था। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां आम जनता रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने बेहद गंभीर तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों की हालत दयनीय हो चुकी है। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा, दवाओं की भारी कमी है और कई जगहों पर मरीजों को घंटों स्टूचर पर इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने इसे “मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी” करार देते हुए कहा



कि सरकार इस दिशा में पूरी तरह विफल रही है। कानून-व्यवस्था को लेकर तेजस्वी

यादव ने अररिया में हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं राज्य में असुरक्षा का

माहौल पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे

खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने सीधे तौर पर Bharatiya Janata Party को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार का गरीब राज्य कहे जाने के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने अपनी सफाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बयान किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं था, बल्कि NITI Aayog की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बेवजह राजनीतिक रंग दिया गया और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव का यह बयान आगामी चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर दिया गया है, जहां वे सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति अपना रहे हैं। अररिया कांड जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाकर उन्होंने कानून-व्यवस्था को केंद्र में ला दिया है, जो किसी भी सरकार के लिए सबसे अहम

कसौटी होती है। हालांकि, सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में यह बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज होगी। जनता के सामने असली सवाल यही है कि इन आरोप-प्रत्यारोपों के बीच उनकी समस्याओं का समाधान कब और कैसे होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में राजनीतिक संघर्ष केवल सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनता के मुद्दों, विकास की दिशा और प्रशासनिक जवाबदेही के इर्द-गिर्द घूम रहा है। आने वाले समय में की रणनीति अपना रहे हैं। अररिया कांड जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाकर उन्होंने कानून-व्यवस्था को केंद्र में ला दिया है, जो किसी भी सरकार के लिए सबसे अहम

छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों के पीछे केवल अपराध की मानसिकता ही नहीं, बल्कि बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और जल्दी पैसा कमाने की चाह भी एक बड़ा कारण है। गांव के कई युवाओं ने पारंपरिक रोजगार के बजाय इस अवैध रास्ते को आसान विकल्प मान लिया है, जो समाज के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। किसी भी अनजान कॉल पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करना, OTP किसी को न बताना और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करना—ये छोटी-छोटी सावधानियां ही बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। कानपुर का यह मामला एक बार फिर यह साबित करता है कि साइबर अपराध अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांवों तक इसकी जड़ फैल चुकी है। जरूरत है सख्त कानून, प्रभावी पुलिसिंग और सबसे बढ़कर जन जागरूकता की, ताकि ऐसे ‘मिनी जामताड़ा’ घनघन से पहले ही खत्म किए जा सकें।

“भोजपुर-बक्सर एमएलसी उपचुनाव का ऐलान 12 मई को मतदान, सियासी सरगर्मी तेज”

भोजपुर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है, जहां विधान परिषद की भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय सीट पर उपचुनाव का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। Election Commission of India द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस सीट के लिए 12 मई को मतदान कराया जाएगा, जबकि 14 मई को मतों की गिनती होगी। इस घोषणा के साथ ही क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है और राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं।

यह सीट 16 नवंबर 2025 से खाली पड़ी थी, जब इस पर काबिज जदयू नेता Radha Charan Sah ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 7 अप्रैल 2028 तक था, लेकिन विधानसभा सदस्य बनने के कारण उन्हें यह सीट छोड़नी पड़ी, जिससे यह उपचुनाव अनिवार्य हो गया।

इस उपचुनाव को केवल एक सीट का चुनाव मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सीधा असर क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक समीकरणों पर पड़ने वाला है। भोजपुर और Buxar क्षेत्र में जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। स्थानीय स्तर पर बैठकें, रणनीति निर्माण और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर



चर्चा तेज हो गई है।

एनडीए गठबंधन, जिसमें Janata Dal (United) प्रमुख भूमिका में है, इस सीट को अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोकने की तैयारी में है। चूंकि यह सीट पहले जदयू के पास थी, इसलिए गठबंधन के लिए इसे बचाना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दूसरी ओर, विपक्षी दल, खासकर Rashtriya Janata Dal, इसे सत्ता पक्ष के खिलाफ जनमत बनाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। इस सीट की खासियत यह है कि यह स्थानीय निकाय से जुड़ी हुई है, इसलिए यहां का चुनावी गणित आम विधानसभा या लोकसभा चुनाव से अलग होता है।

इसमें मतदाता सीधे आम जनता नहीं, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं—जैसे पंचायत सदस्य, वार्ड पार्षद, जिला परिषद सदस्य आदि। ऐसे में यहां जातीय समीकरणों के साथ-साथ स्थानीय नेटवर्क और संगठनात्मक पकड़ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर पिछले चुनाव की बात करें, तो Radha Charan Sah की जीत ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचा था। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने संदेश सीट से महज 27 वोटों के बेहद कम अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने Deepu Singh को हराया था और कुल 80,598 वोट प्राप्त किए थे। यह मुकाबला

इतना रोमांचक था कि इसे बिहार के सबसे करीबी चुनावी मुकाबलों में गिना गया। अब वही क्षेत्र एक बार फिर चुनावी मैदान में है, जहां हर दल अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और दलों की जमीनी पकड़ निर्णायक भूमिका निभाएगी।

इस बीच, आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। मतदान केंद्रों की पहचान, कर्मियों की तैनाती और अन्य तैयारियां तेज गति से चल रही हैं।

आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सा दल इस सीट पर अपना कब्जा जमाने में सफल होता है। क्या एनडीए अपनी सीट बचा पाएगा या विपक्ष इस मौके को भुनाकर सत्ता पक्ष को झटका देगा—यह सवाल अब चुनावी चर्चा का केंद्र बन चुका है। फिलहाल, इतना तय है कि भोजपुर-बक्सर का यह उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की सियासत का एक अहम संकेत बनने जा रहा है, जहां से भविष्य के राजनीतिक रुझानों की झलक साफ दिखाई दे सकती है।

“कानपुर का ‘मिनी जामताड़ा’: रटि गांव में 12वीं फेल युवाओं का साइबर टगी साम्राज्य, हजारों लोग बने शिकार”

कानपुर। देश में साइबर अपराध के बढ़ते जाल के बीच उत्तर प्रदेश का कानपुर अब एक नए ‘जामताड़ा’ के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। जिले के रेडना क्षेत्र का रटि गांव इन दिनों साइबर टगी के संगठित नेटवर्क के कारण सुर्खियों में है, जहां कम पढ़े-लिखे लेकिन बेहद चालाक युवाओं ने तकनीक का इस्तेमाल कर टगी का ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया है, जिसने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। झारखंड के Jamtara की तरह अब रटि गांव का नाम भी साइबर टगी के लिए चर्चाओं में शामिल हो गया है। यहां पिछले लगभग एक दशक से टगी का यह खेल लगातार चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, गांव के कई युवक सुबह होते ही मोबाइल फोन और लैपटॉप के साथ इस ‘काम’ में लग जाते हैं और देर रात तक देश के अलग-अलग हिस्सों में बैठे लोगों को अपना शिकार बनाते रहते हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन युवाओं में से कई सिर्फ 10वीं या 12वीं तक ही पढ़े हैं, लेकिन उनकी बोलचाल, आत्मविश्वास और तकनीकी समझ इतनी तेज है कि वे बड़े-बड़े अधिकारियों, व्यापारियों और आम लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये लोग खुद को बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर एजेंट या सरकारी



कर्मचारी बताकर लोगों से OTP, बैंक डिटेल और अन्य संवेदनशील जानकारी हासिल कर लेते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस गांव से जुड़े साइबर टगी ने अब तक देशभर में 4000 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया है और करोड़ों रुपये की टगी को अंजाम दिया है। यह आंकड़ा केवल सामने आए मामलों का है, जबकि असल संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि कई लोग शर्म या डर के कारण शिकायत ही दर्ज नहीं कराते। इस पूरे नेटवर्क की खासियत इसकी संगठित संरचना है। गांव में अलग-अलग

भूमिकाएं तय होती हैं—कुछ लोग कॉल करने का काम करते हैं, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन को संभालते हैं, जबकि कुछ लोग फर्जी सिम कार्ड और खातों की व्यवस्था करते हैं। इस तरह यह पूरा सिस्टम एक ‘मिनी कॉल सेंटर’ की तरह काम करता है, जहां हर सदस्य की जिम्मेदारी तय होती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर टगी का यह कारोबार लंबे समय से चल रहा था, लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई बेहद सीमित रही। हालांकि अब पहली बार पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए

छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों के पीछे केवल अपराध की मानसिकता ही नहीं, बल्कि बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और जल्दी पैसा कमाने की चाह भी एक बड़ा कारण है। गांव के कई युवाओं ने पारंपरिक रोजगार के बजाय इस अवैध रास्ते को आसान विकल्प मान लिया है, जो समाज के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। किसी भी अनजान कॉल पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करना, OTP किसी को न बताना और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करना—ये छोटी-छोटी सावधानियां ही बड़े नुकसान से बचा सकती हैं।

कानपुर का यह मामला एक बार फिर यह साबित करता है कि साइबर अपराध अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांवों तक इसकी जड़ फैल चुकी है। जरूरत है सख्त कानून, प्रभावी पुलिसिंग और सबसे बढ़कर जन जागरूकता की, ताकि ऐसे ‘मिनी जामताड़ा’ घनघन से पहले ही खत्म किए जा सकें।

“सरकारी खजाने पर बड़ा वार: 550 करोड़ के बैंक घोटाले ने खोली सिस्टम की परतें”

नई दिल्ली। देश की बैंकिंग और सरकारी वित्तीय व्यवस्था को झकझोर देने वाला एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें हरियाणा सरकार के खातों से कथित तौर पर 550 करोड़ रुपये के गनब का मामला उजागर हुआ है। इस सनसनीखेज प्रकरण में Central Bureau of Investigation ने एफआईआर दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली है। मामला IDFC First Bank की चंडीगढ़ शाखा से जुड़ा हुआ है, जहां सरकारी धन के दुरुपयोग और सुनियोजित वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला केवल एक साधारण बैंकिंग गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक अपराध के रूप में सामने आया है, जिसमें सरकारी फंड को व्यवस्थित तरीके से फर्जी खातों और निजी संस्थाओं में ट्रांसफर किया गया। प्रारंभिक जांच और सूत्रों के अनुसार, यह घूरा खल लंबे समय

से चल रहा था और इसमें कई स्तरों पर मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब हरियाणा सरकार के सतर्कता विभाग ने संदिग्ध लेनदेन पर ध्यान दिया। जांच के दौरान यह पाया गया कि सरकारी विभागों द्वारा जो धन बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (SFD) के रूप में जमा किया जाना था, उसे नियमों के विरुद्ध अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। यह ट्रांसफर किसी एक या दो बार नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से बार-बार किया गया, जिससे कुल मिलाकर लगभग 550 करोड़ रुपये का गनब हो गया।

हरियाणा सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे पहले State Vigilance and Anti Corruption Bureau Haryana को सौंपा था। इस एजेंसी ने प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने लाए। इसके बाद मामला केंद्र



सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास भेजा गया, जहां से इसे Central Bureau of Investigation को सौंप दिया गया। सीबीआई ने मामले को अपने

हाथ में लेते ही एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस घोटाले को अंजाम देने के लिए कई फर्जी कंपनियों

और संस्थाओं का इस्तेमाल किया गया। इनमें स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट, एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड, कैप को फिनटेक सर्विसेज, आरएस ट्रेडर्स

और अन्य संबंधित फर्म शामिल हैं। इन संस्थाओं के खातों में सरकारी धन को ट्रांसफर किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से किया गया अपराध था। इस घोटाले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसमें बैंकिंग सिस्टम की धमियों का फायदा उठाया गया। सरकारी धन, जो सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित था, उसे निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। यह न केवल वित्तीय अनियमितता है, बल्कि जनता के विश्वास के साथ भी धोखा है।

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले में बैंक के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। बिना अंदरूनी सहयोग के इतनी बड़ी राशि का इस तरह ट्रांसफर होना लगभग असंभव है। जांच एजेंसियों अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि किन-किन स्तरों पर यह मिलीभगत हुई

और इसमें कितने लोग शामिल हैं। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका भी इस मामले में महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हो सकता है। यदि यह साबित होता है कि गनब की गई राशि को अवैध तरीकों से छिपाने या निवेश करने की कोशिश की गई, तो Enforcement Directorate भी इस जांच में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। इस घोटाले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर सरकारी धन की सुरक्षा के लिए बनाए गए सिस्टम कितने मजबूत हैं। जब इतनी बड़ी राशि बिना किसी संदेह के लंबे समय तक ट्रांसफर होती रही, तो यह स्पष्ट है कि निगरानी तंत्र में कहीं न कहीं गंभीर कमी रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और निगरानी को और मजबूत करना होगा। डिजिटल ट्रैकिंग, ऑडिट सिस्टम और रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का प्रभावी उपयोग जरूरी है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। इस घटना का असर केवल हरियाणा या संबंधित बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के बैंकिंग और प्रशासनिक ढांचे के लिए एक चेतावनी है। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो इस तरह के आर्थिक अपराध भविष्य में और बढ़ सकते हैं। फिलहाल, Central Bureau of Investigation इस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। दस्तावेजों की जांच, बैंक रिकॉर्ड का विश्लेषण और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ जारी है।

भरा हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट होती है कि शोयर बाजार केवल देश के आर्थिक आंकड़ों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वैश्विक परिस्थितियों का भी उस पर गहरा असर पड़ता है। जब दुनिया के किसी भी हिस्से में तनाव बढ़ता है, तो उसका असर सीमाओं से परे जाकर हर बाजार में महसूस किया जाता है। अंततः, गुरुवार की यह गिरावट निवेशकों को यह संदेश देती है कि बाजार में स्थिरता हमेशा नहीं रहती। उतार-चढ़ाव इसका स्वाभाविक निवेशकों के लिए यह गिरावट अपने साथ धैर्य और विवेक के साथ निवेश किया जा सकता है। हालांकि, बिना नए अवसर भी लेकर आती है।

“भू-राजनीतिक तनाव और मुनाफावसूली का असर: सेंसेक्स 931 अंक टूटा, निवेशकों में बढ़ी चिंता”

मुंबई। गुरुवार का कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए भारी उतार-चढ़ाव और अंततः गुरु गिरावट लेकर आया। देश के प्रमुख सूचकांक BSE Sensex में 931 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह 76,632 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 भी 222 अंक फिसलकर 23,775 पर आ गया। यह गिरावट केवल एक दिन की सामान्य हलचल नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे कारण थे, जिन्होंने निवेशकों के मन में अस्थिरता और डर दोनों पैदा कर दिए। दिनभर के कारोबार के दौरान बाजार में शुरू से ही दबाव देखा गया। शुरुआती घंटों में हल्की रिक्तरी की उम्मीद जरूर बनी, लेकिन जैसे-जैसे

दिन आगे बढ़ा, बिकवाली का दबाव बढ़ता गया और बाजार निचले स्तरों पर बंद हुआ। खासतौर पर ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिली, जिसने बाजार की रीढ़ को कमजोर कर दिया। बड़े बैंकिंग शेयरों में गिरावट का असर पूरे इंडेक्स पर पड़ा, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा होता है। वहीं, ऑटो सेक्टर पर बढ़ती लागत और मांग को लेकर चिंता का असर साफ दिखाई दिया। हालांकि, पूरी तस्वीर नकारात्मक नहीं रही। मेटल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में कुछ मजबूती देखने को मिली। मेटल कंपनियों को वैश्विक कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव से फायदा मिला, जबकि फार्मा सेक्टर को एक डिफेंसिव निवेश विकल्प



के रूप में देखा गया। जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक अक्सर फार्मा जैसे सेक्टर की ओर रुझ कर लेते हैं, जिससे वहां खरीदारी बढ़ती है। इस गिरावट के पीछे सबसे प्रमुख कारण वैश्विक भू-राजनीतिक

तनाव रहा। Lebanon में हालिया घटनाओं और हमलों के बाद Iran और United States के बीच तनाव बढ़ गया है। पहले जहां दोनों देशों के बीच सीजफायर की उम्मीद थी, अब वह कमजोर पड़ती नजर

आ रही है। इस स्थिति ने वैश्विक निवेशकों के बीच असमंजस और भय का माहौल बना दिया है। जब भी दुनिया में इस तरह का तनाव बढ़ता है, तो निवेशक जोखिम भरे एसेट्स से दूरी बनाते हैं और सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ते हैं, जिससे शेयर बाजार में गिरावट आती है। दूसरी बड़ी वजह तेल बाजार से जुड़ी है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक Strait of Hormuz अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। यहां टैकरो की आवाजाही प्रभावित होने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। भारत जैसे देश, जो अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता

है, उसके लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील होती है। तेल महंगा होने से कंपनियों की लागत बढ़ती है, महंगाई का दबाव बनता है और आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि निवेशकों ने सतर्कता बरतते हुए बाजार से दूरी बनानी शुरू कर दी। हाल ही में United States और Iran के बीच दो हफ्ते के सीजफायर की खबरों के बाद भारतीय बाजार में लगभग 4% की तेज उछाल आई है। इस तेजी के बाद कई निवेशकों ने अपने मुनाफे को सुरक्षित करना बेहतर समझा और शेयर बेचने शुरू कर दिए। इस बिकवाली ने बाजार पर और दबाव बढ़ा दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार

फिलहाल बाहरी कारकों के प्रभाव में है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की गतिविधियां, डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक राजनीतिक घटनाएं—ये सभी मिलकर बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे माहौल में छोटी-छोटी खबरों भी बड़े उतार-चढ़ाव का कारण बन सकती हैं। निवेशकों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है। अल्पकालिक निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। वहीं, दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह गिरावट अपने साथ अवसर भी बन सकती है, जहां वे मजबूत कंपनियों में उचित मूल्य पर निवेश कर सकते हैं। हालांकि, बिना विश्लेषण के निवेश करना जोखिम

भरा हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट होती है कि शेयर बाजार केवल देश के आर्थिक आंकड़ों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वैश्विक परिस्थितियों का भी उस पर गहरा असर पड़ता है। जब दुनिया के किसी भी हिस्से में तनाव बढ़ता है, तो उसका असर सीमाओं से परे जाकर हर बाजार में महसूस किया जाता है। अंततः, गुरुवार की यह गिरावट निवेशकों को यह संदेश देती है कि बाजार में स्थिरता हमेशा नहीं रहती। उतार-चढ़ाव इसका स्वाभाविक निवेशकों के लिए यह गिरावट अपने साथ धैर्य और विवेक के साथ निवेश किया जा सकता है। हालांकि, बिना नए अवसर भी लेकर आती है।

“बुनकरों को बड़ी राहत: बिजली बिल में कमी की तैयारी, योगी सरकार का फोकस ‘लागत घटाओ—आय बढ़ाओ’ पर”

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों बुनकरों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने उनकी लंबे समय से चली आ रही सबसे बड़ी समस्या—बिजली के बढ़ते बिल—पर गंभीर पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पावरलूम बुनकरों के बिजली बिल को कम करने के लिए एक व्यवहारिक, प्रभावी और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाए। यह कदम न केवल बुनकरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि प्रदेश के पारंपरिक उद्योग को नई ऊर्जा भी देगा। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश हथकरघा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए, जिसमें अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका सीधा लाभ बुनकरों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुनकर केवल परंपरा के संवाहक नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ हैं। ऐसे में उनकी आय, सम्मान और आजीविका की स्थिरता सुनिश्चित करना सरकार की

प्राथमिक जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में बुनकारी केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। वाराणसी की सिल्क साड़ियां, थदोही के कालीन, मिर्जापुर की दरियां और कई अन्य उत्पाद न केवल देश में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र से जुड़े लाखों परिवार आज भी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या बिजली की लागत है। पावरलूम उद्योग पूरी तरह बिजली पर निर्भर होता है। ऐसे में जब बिजली के दाम बढ़ते हैं, तो इसका सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ता है। इससे बुनकरों का मुनाफा घटता है और कई बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। यही वजह है कि लंबे समय से बुनकर बिजली बिल में राहत की मांग कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देश के बाद इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार ने इस समस्या का समाधान केवल



सब्सिडी तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि दीर्घकालिक सोच के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि बुनकर सौर ऊर्जा अपनाते हैं, तो उनकी बिजली पर निर्भरता कम होगी और लंबे समय में उनकी लागत

में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके लिए एक समग्र योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सोलर पैनल की स्थापना, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग शामिल होगा। यह पहल न केवल आर्थिक दृष्टि से

फायदेमंद होगी, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से प्रदूषण में कमी आएगी और उद्योग को टिकाऊ विकास की दिशा मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना को सही

तरिके से लागू किया गया, तो यह पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकती है। हालांकि, बुनकरों की समस्याएं केवल बिजली बिल तक सीमित नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में इस बात को भी स्वीकार किया कि इस क्षेत्र के सामने कई अन्य गंभीर, आधुनिक डिजाइन और तकनीकी कमी, सीमित बाजार पहुंच और वित्तीय संसाधनों की कमी—ये सभी समस्याएं मिलकर बुनकरों की प्रगति में बाधा बन रही हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्लस्टर आधारित विकास मॉडल पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने निर्देश दिए कि बुनकर बहुल क्षेत्रों की पहचान कर वहां क्लस्टर विकसित किए जाएं। इन क्लस्टरों में उत्पादन से लेकर विपणन तक की पूरी प्रक्रिया को एकीकृत किया जाएगा, जिससे बुनकरों को हर स्तर पर सहयोग मिल सके। क्लस्टर मॉडल के तहत बुनकरों को एक संगठित इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां उन्हें आधुनिक मशीनों, बेहतर डिजाइन, प्रशिक्षण और बाजार

से सीधा जुड़ाव मिलेगा। इससे न केवल उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि उनकी प्रतिस्पर्धामुक्तता भी बढ़ेगी। साथ ही, सामूहिक उत्पादन और विपणन के कारण लागत में भी कमी आएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1.99 लाख बुनकर कार्यरत हैं और यह राज्य इस क्षेत्र में देश में छठवें स्थान पर है। कालीन, दरी और मैट के उत्पादन में प्रदेश अग्रणी है, जबकि बेडशेडिंग, फर्निशिंग और ब्लैकेट जैसे उत्पादों में भी इसकी मजबूत उपस्थिति है। वर्ष 2024-25 में देश के कुल हथकरघा निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 9.27 प्रतिशत रहा, जो इस क्षेत्र की संभावनाओं को दर्शाता है। सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है। क्लस्टर के भीतर डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे बुनकरों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिल सके। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा

रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक क्लस्टर के लिए बेसलाइन सर्वे किया जाए और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाए। इसके बाद प्रभावी क्रियान्वयन और सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तव में बुनकरों तक पहुंचे। यह पहल ऐसे समय में की जा रही है, जब पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच खुद को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में सरकार का यह कदम बुनकरों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो इससे न केवल बुनकरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही, यह पहल ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने और पारंपरिक कला को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंततः, यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल केवल एक आर्थिक योजना नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा में उठाया गया कदम है।

“बिहार की विरासत को डिजिटल पंख: 4.7 लाख प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण का महाअभियान तेज”



पटना। बिहार, जिसे प्राचीन काल से ही ज्ञान, दर्शन और विद्या की भूमि के रूप में जाना जाता रहा है, अब अपनी उसी ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तकनीक के सहारे सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। राज्य में 75 वर्ष से अधिक पुरानी कुल 4,71,802 पांडुलिपियों की पहचान कर उनके संरक्षण और डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह पहल न केवल अतीत को संभालने का प्रयास है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के खजाने को सुरक्षित रखने की एक दूरदर्शी योजना भी है।

इस महत्वाकांक्षी अभियान के पीछे केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना Gyan Bharatam Mission की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके तहत देशभर में बिखरी प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, वैज्ञानिक संरक्षण और डिजिटलीकरण किया जा रहा है। बिहार इस मिशन में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जहां बड़े पैमाने पर यह कार्य संगठित रूप से किया जा रहा है। जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो Madhubani इस सूची में सबसे आगे है, जहां अकेले 3,70,926 पांडुलिपियों की पहचान की गई है। इसके अलावा Patna, Darbhanga और Nalanda जैसे जिले भी इस मामले में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि बिहार सदियों से ज्ञान, साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है। इन पांडुलिपियों की खासियत यह है

कि ये विभिन्न माध्यमों पर संरक्षित हैं—कागज, ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़ा और यहां तक कि धातु पर भी लिखी गई पांडुलिपियां इस संग्रह का हिस्सा हैं। इनमें धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, साहित्य और इतिहास जैसे विषयों से जुड़ी अमूल्य जानकारीयें निहित हैं। कई पांडुलिपियां ऐसी भी हैं, जिनमें अब तक अज्ञात या कम ज्ञात ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। इस पूरे अभियान को गति देने के लिए राज्य के प्रमुख शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों को केंद्र बनाया गया है। Nava Nalanda Mahavihara, Khuda Bakhsh Oriental Public Library और Bodh Gaya स्थित मठों को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। ये संस्थान न केवल पांडुलिपियों की पहचान और सूचीकरण कर रहे हैं, बल्कि उनके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का भी उपयोग कर रहे हैं।

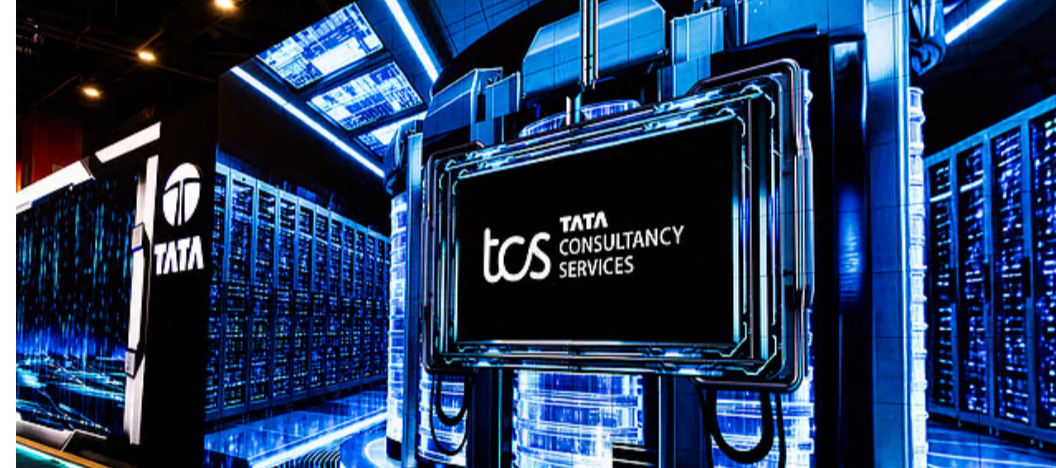
डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के तहत इन पांडुलिपियों को उच्च गुणवत्ता वाले स्कैनर से डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित किया जा रहा है। इससे दो बड़े लाभ होंगे—पहला, मूल पांडुलिपियां सुरक्षित रहेंगी और उनका क्षरण रोका जा सकेगा; दूसरा, शोधकर्ताओं और आम लोगों को इन तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर के विद्वान अब दस्तावेजों का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल केवल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के पुनरुत्थान (revival) का भी माध्यम बन सकती है। कई पांडुलिपियों में ऐसे अमूल्य जानकारियां निहित हैं। यदि इनका सही तरीके से अध्ययन किया जाए, तो यह आधुनिक विज्ञान और समाज के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। हालांकि, इस कार्य के सामने कई चुनौतियां भी हैं। पुरानी पांडुलिपियों की स्थिति कई बार इतनी खराब होती है कि उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञों और अत्याधुनिक उपकरणों की जरूरत होती है। इसके अलावा, कई पांडुलिपियां निजी संग्रहों में भी हैं, जिन्हें सामने लाना और संरक्षित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। राज्य सरकार और संबंधित संस्थान इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग अपने पास मौजूद पुरानी पांडुलिपियों की जानकारी साझा करें और उन्हें संरक्षण के लिए उपलब्ध कराएं।

यह पहल बिहार के गौरवशाली अतीत को संजोने के साथ-साथ भविष्य के लिए ज्ञान का एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। जब ये इन दस्तावेजों का अध्ययन कर सकते हैं, जिन्हें हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया। सहकर्मियों के बीच उनकी छवि एक जिम्मेदार, शांत और समर्पित अधिकारी की थी। वह अपने काम को केवल नौकरी नहीं, बल्कि सेवा मानते थे। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। साथी अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखें नम हैं। हर कोई यही कह रहा है कि मोनु कुमार जैसे अधिकारी बहुत कम होते हैं, जो बिना किसी दिखावे के पूरी लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनके

“मजबूत प्रदर्शन के साथ टीसीएस ने चौथी तिमाही में दिखाया दम, 13,718 करोड़ मुनाफे के साथ निवेशकों को राहत”

मुंबई। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी रहता, महंगाई के दबाव और तकनीकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के नए दौर से गुजर रही है, ऐसे समय में भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी Tata Consultancy Services ने अपने चौथी तिमाही के नतीजों से यह साबित कर दिया है कि मजबूत रणनीति, तकनीकी नवाचार और वैश्विक भरपूर के बल पर निरंतर विकास संभव है। कंपनी ने वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में 13,718 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 12,224 करोड़ की तुलना में 12% अधिक है। यह वृद्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस भरपूर और स्थिरता का प्रतीक है, जो टीसीएस ने वर्षों में अपने ग्राहकों और निवेशकों के बीच बनाई है। इस तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू भी 10% की वृद्धि के साथ 70,698 करोड़ तक पहुंच गया। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि कंपनी ने न केवल अपने मौजूदा क्लाइंट बेस को बनाए रखा, बल्कि नए अवसरों को भी सफलतापूर्वक अपनाया। विशेष रूप से 12 अरब डॉलर (करीब 1 लाख करोड़) की तीन बड़ी मेगा डीलसे न इस ग्रोथ में निष्णात कर्मियों का निभाई। ये डीलसे दर्शाती हैं कि वैश्विक कंपनियों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अब भी टीसीएस पर भरोसा कर रही हैं।



टीसीएस की इस सफलता के पीछे उसकी दीर्घकालिक रणनीति का बड़ा योगदान है। कंपनी के CEO और MD K Krithivasan ने बताया कि “फाइव पिलर स्ट्रेटजी” के तहत कंपनी क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में लगातार निवेश कर रही है। खासतौर पर AI के क्षेत्र में तेजी से बढ़ते अवसरों को देखते हुए टीसीएस ने अपने संसाधनों और विशेषज्ञता को इस दिशा में केंद्रित किया है। यही कारण है कि कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए एफ डेस्टावेज संधिध पाए गए।

सीमित नहीं रही बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, हेल्थकेयर, रिटेल, मैन्यूफैक्चरिंग और कर्म्युनिकेशन जैसे लगभग सभी सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अमेरिका, यूरोप और एशिया-पैसिफिक जैसे प्रमुख बाजारों में भी कंपनी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। इस व्यापक विस्तार ने टीसीएस को एक संतुलित और स्थिर ग्रोथ मॉडल प्रदान किया है, जो उसे अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाता है। कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए भी आकर्षक घोषणा की है। Tata Consultancy Services ने प्रति शेयर 31 के लाभांश का ऐलान किया है। यह निर्णय कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है और यह भी संकेत देता है

कि टीसीएस अपने शेयरधारकों के हितों को प्राथमिकता देती है। निवेशकों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है, खासकर ऐसे समय में जब बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि, शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन भीमिश्रित रहा है। 9 अप्रैल को टीसीएस का शेयर 1.20% की बढ़त के साथ 2,590 पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में इसमें हल्की तेजी देखी गई है, लेकिन यदि एक साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो शेयर करीब 20% तक गिर चुका है। इस गिरावट के पीछे वैश्विक आईटी सेक्टर में मंदी, क्लाइंट्स के खर्च में कटौती और निवेशकों की सतर्कता जैसे कारण माने जा रहे हैं। फिर भी, ताजा नतीजों ने बाजार में

सकारात्मक माहौल बनाने में मदद की है। कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू लगभग 11.71 लाख करोड़ बनी हुई है, जो इसे भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाती है। यह आंकड़ा न केवल कंपनी की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, बल्कि भविष्य में उसके संभावित विकास की भी झलक देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती मांग टीसीएस के लिए नए अवसर पैदा करेगी। हालांकि, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और प्रतिस्पर्धा के बढ़ते दबाव को देखते हुए कंपनी को अपनी रणनीतियों में निरंतर सुधार करते रहना होगा। इस पूरे परिदृश्य में Tata Consultancy Services का नेतृत्व स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मजबूत नेतृत्व, प्रयत्न दृष्टिकोण और तकनीकी नवाचार के बल पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। टीसीएस ने न केवल अपने वर्तमान को मजबूत किया है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक ठोस आधार तैयार किया है। अंततः, यह कहा जा सकता है कि चौथी तिमाही के ये नतीजे केवल वित्तीय आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह उस भरपूर, मेहनत और दूरदर्शिता की कहानी है, जिसने टीसीएस को वैश्विक आईटी क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय ब्रांड बनाया है।

“हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला: 15 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी से मचा हड़कंप, सिस्टम की पोल खुली”

हजारीबाग। झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है, जहां Hazaribagh ट्रेजरी से 15 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध निकासी का चौकाने वाला मामला सामने आया है। इस खुलासे ने न केवल सरकारी वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि सिस्टम के भीतर गहरी खामियां मौजूद हैं, जिनका लंबे समय तक उपलब्ध किया जाता रहा। प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं। बताया जा रहा है कि यह कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित और संगठित तरीके से किया गया वित्तीय घोटाला है, जो लंबे समय से जारी था। फर्जी बिलों, जाली दस्तावेजों और लेखा प्रणाली की कमजोरियों का सहारा लेकर करोड़ों रुपये

सरकारी खजाने से निकाल लिए गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी रकम की निकासी लंबे समय तक बिना किसी ठोस संदेह के होती रही। मामला तब उजागर हुआ जब नियमित वित्तीय ऑडिट के दौरान कुछ संदिग्ध लेन-देन पर अधिकारियों की नजर पड़ी। इसके बाद जब गहराई से जांच की गई, तो धीरे-धीरे इस घोटाले की परतें खुलने लगीं। ऑडिट रिपोर्ट में कई ऐसे भुगतान दर्ज मिले, जिनके समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस पूरे मामले में कई स्तरों पर मिलीभगत रही है। बिना अंदरूनी सहयोग के इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता संभव नहीं मानी जा रही। यही वजह है कि अब जांच का दायरा केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उच्च पदों पर

बैठे अधिकारियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। सूत्रों के अनुसार, जिन दस्तावेजों के आधार पर भुगतान किए गए, उनमें कई खामियां पाई गई हैं—जैसे फर्जी हस्ताक्षर, गलत स्वीकृति पत्र, और ऐसे बिल जो वास्तविक कार्य या अपूर्ण से मेल नहीं खाते। इससे यह स्पष्ट होता है कि सिस्टम के भीतर निगरानी और सत्यापन की प्रक्रिया बेहद कमजोर रही है। वर्तमान में कई कर्मचारियों और अधिकारियों को जांच के दायरे में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और मामले में कई स्तरों पर मिलीभगत की जा रही है। इसके साथ ही, संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन-किन स्तरों पर नियमों की अनदेखी की गई।

इस घोटाले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी ट्रेजरी जैसी संवेदनशील व्यवस्था में निगरानी तंत्र इतना कमजोर कैसे हो सकता है। जहां हर भुगतान के लिए एक महीने में सत्यापन की प्रक्रिया होती है, वहां इतनी बड़ी रकम का गनब होना सिस्टम की गंभीर विकलता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सिस्टम में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। डिजिटल ट्रैकिंग, रियल-टाइम ऑडिट, और पारदर्शी भुगतान प्रणाली जैसे उपाय अपनाकर ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। राज्य सरकार के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। एक ओर जहां दोषियों के खिलाफ कड़ी

कार्रवाई की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर सिस्टम को दुरुस्त करने का दबाव भी बढ़ गया है। आम जनता के बीच भी इस घटना को लेकर नाराजगी है, क्योंकि यह पैसा अंततः जनता के टैक्स से ही आता है। अब सबकी नजर जांच के अंतिम निष्कर्ष पर टिकी है। क्या इस घोटाले के सभी जिम्मेदार लोगों को बेकाबू किया जाएगा? क्या सिस्टम में जरूरी सुधार किए जाएंगे? ये सवाल आने वाले समय में राज्य की प्रशासनिक साधों को तय करेंगे। यह मामला केवल एक घोटाले की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है—कि यदि निगरानी और जवाबदेही को मजबूत नहीं किया गया, तो इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आती रहेंगी और सरकारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा लगातार कमजोर होता जाएगा।

“इयूटी पर जा रहे दरोगा को ट्रक ने कुचला, रास्ते में ही टूट गई जिंदगी की डोर”

अरवल। बिहार के Arwal जिले की सड़कों पर गुरुवार का दिन एक ऐसी सुलिस विभाग को बिल्क पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। 2020 बैच के युवा दरोगा Monu Kumar, जो अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। वह अपने वरीय अधिकारियों के बलुवे पर मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का अंतिम सफर बन जाएगा। यह घटना Rampur Chauram police station area के अंतर्गत आने वाले सुखी बिगाहा गांव के पास घटी। सुबह का समय था, जब दरोगा मोनु कुमार अपनी बाइक से तेजी से नहीं, बल्कि सामान्य गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़

रहे थे। लेकिन अचानक सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह सड़क पर दूर जा गिरे। टक्कर की आवाज इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए और कुछ ही क्षणों में घटनास्थल पर भाड़ इकट्ठा हो गई। हादसे के बाद का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। सड़क पर खून से लथपथ पड़े दरोगा मोनु कुमार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए इस्थानियत का परिचय दिया और तुरंत उन्हें उठाकर Sadar Hospital Arwal पहुंचाया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। सिर में गहरी चोट, शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर और अत्यधिक रक्तस्राव ने स्थिति को बेहद



नाजुक बना दिया। डॉक्टरों ने तुरंत बेहतर इलाज के लिए उन्हें AIIMS Patna रेफर किया। एंबुलेंस में

उन्हें पटना ले जाया जा रहा था, परिवार को सूचना दी जा चुकी थी, साथी पुलिसकर्मी भी बचेन थे और हर कोई यही दुआ कर रहा

था कि वह किसी तरह बच जाएं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था—पटना पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी सांस

थम गई। एक होनहार अधिकारी, एक बेटे, एक सपने देखने वाले इंसान की जिंदगी यूं अचानक खत्म हो गई। दरोगा मोनु कुमार का जीवन संघर्ष और मेहनत की मिसाल था। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर पुलिस सेवा में जगह बनाई थी। 2020 बैच में चयनित होने के बाद चालक की लापरवाही सामने को पूरी ईमानदारी से निभाया। सहकर्मियों के बीच उनकी छवि एक जिम्मेदार, शांत और समर्पित अधिकारी की थी। वह अपने काम को केवल नौकरी नहीं, बल्कि सेवा मानते थे। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। साथी अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखें नम हैं। हर कोई यही कह रहा है कि मोनु कुमार जैसे अधिकारी बहुत कम होते हैं, जो बिना किसी दिखावे के पूरी लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनके

निधन ने विभाग को एक बड़ी क्षति पहुंचाई है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। दूसरी ओर, इस हादसे ने सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार, लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी आज भी देश की सड़कों पर मौत सेवा में जगह बनाई थी। 2020 बैच में चयनित होने के बाद चालक की लापरवाही सामने को पूरी ईमानदारी से निभाया। सहकर्मियों के बीच उनकी छवि एक जिम्मेदार, शांत और समर्पित अधिकारी की थी। वह अपने काम को केवल नौकरी नहीं, बल्कि सेवा मानते थे। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। साथी अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखें नम हैं। हर कोई यही कह रहा है कि मोनु कुमार जैसे अधिकारी बहुत कम होते हैं, जो बिना किसी दिखावे के पूरी लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनके

दुनिया में नहीं रहा। उनकी शहादत ने एक बार फिर यह एहसास दिलाया है कि इयूटी पर निकला हर जवान हर पल जोखिम से जूझता है। यह घटना केवल एक सड़क हादसा नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है—कि सड़क पर एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है। यह समय है कि हम सभी यातायात नियमों का पालन करें, जिम्मेदारी से वाहन चलाएं और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। अंततः, दरोगा मोनु कुमार भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कर्तव्यनिष्ठा, उन्का समर्पण और उनका संघर्ष हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो इस राह पर चलते हैं, वे हमेशा सम्मान और श्रद्धा के पात्र बनते हैं।